उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-2021

1. राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक-वित्त

मुख्य बिन्दु

• वर्ष 2019-20 में स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8%,एवं प्रचलित भावों पर 6.5% रही है।

• वर्ष 2019-20 के स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय रू 44618 एवं प्रचलित भावों पर रू 65704 आंकलित हुई है, जो गत वर्ष से वृद्धि दर क्रमशः 2.2% एवं 4.9 % को दर्शाता है।

• वर्ष 2019-20 में स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 1.9%, -0.5%, 7.7% एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 6.3%, 0.6%, 8.9% रही है।

• वर्ष 2019-20 में स्थायी भावों पर जीएसवीए का खण्डवार वितरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.0, 26.8 एवं 50.0 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 25.3, 24.9, एवं 49.7 प्रतिशत रही है।

• वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 39.5 प्रतिशत है, जबकि वैट का अंश लगभग 16.7 प्रतिशत है।

• वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में पूंजीगत परिव्यय में शत-प्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया, बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है, जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

• वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है।

• राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में 2.63 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2018-19 में घटकर 2.38 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है।

byjusexamprep.com

2. प्रादेशिक विकास में चुनौतियाँ एवं रणनीति

"आत्मनिर्भरता में लाखों चुनौतियाँ, किन्तु करोड़ों समाधान"

मुख्य बिन्दु

• प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक सेक्टर में अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है।

• ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया।

• विगत् वर्षों में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया।

• प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

• महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की गयी है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगा।

• नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" का गठन किया गया है।

• वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की 87.96 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी।

3. बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

मुख्य बिन्दु

byjusexamprep.com

• बैंकिंग नेटवर्क मार्च, 2020 तिमाही मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग किमी से बढ़कर औसतन 2.28 वर्ग किमी हो गया है।

• वित्तीय वर्ष 2020-21 में समीक्षा अवधि जून 2020 तक कुल 7,68871 किसान केडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

• कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण क्रमशः 25.98%, 58.34% एवं 18.94% है।

• एम.एस.एम.ई/ व्यावसायिक ईकाईयों/कृषकों/समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' की घोषणा की गयी है।

• प्रदेश प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत देश मे सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते (16.48 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

4. कृषि, वन एवं पर्यावरण

मुख्य बिन्दु

• किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया।

• उत्तर प्रदेश, किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।

• वर्ष 2018-2019 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604 लाख 15 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है।

• कृषि श्रमिको की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक

byjusexamprep.com

की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

• कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, लखीमपुर-खीरी में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

• प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

5. पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

मुख्य बिन्दु

• वर्ष 2019-20 में प्रदेश मे 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है।

• माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेक्शन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु पीसीडीएफ व एनडीडीबी द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारम्भ किया गया है। पीसीडीएफ द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली को एनडीडीबी द्वारा मिल्क डे (1 जून, 2018) पर इनोवेशन एवार्ड दिया गया।

• मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद व झांसी में विटामिन ए व डी युक्त फोर्टीफाइड पराग दुग्ध का विक्रय प्रारम्भ कराया गया है।

• प्रदेश के 5 जनपदों में पायलट बेस पर दुग्ध पट्टी पर पशु चिकित्सा सुविधा, दवाई आदि हेतु सी0एस0आर0 कॉल सेन्टर (1800 102 2017) स्थापित किये गये हैं।

• प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया है।

byjusexamprep.com

6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्य बिन्दु

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

• प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

• वर्ष 2020-21 में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम हेतु 812.61 करोड़ रू का बजट प्राविधान किया गया है, जो प्रदेश सरकार के कुल बजट 512860 करोड रू का 0.16 प्रतिशत है।

• प्रदेश में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2019-20 मे 579.37 करोड़ रू व्यय किया।

• वर्ष 2017-18 में आलू, आम एवं अमरुद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा।

• देश के कुल आम उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20.86 प्रतिशत था।

7. ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

मुख्य बिन्दु

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

• प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर रू 182/-प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर रू 201/- निर्धारित कर दी गई है।

byjusexamprep.com

• वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के 592 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सितम्बर, 2020 तक 14.30 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना के परफार्मेन्स इंडेक्स में प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है।

• मुख्यमत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16700 एवं 2019-20 में कुल 34040 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है।

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग हैं एवं कार्यदायी विभाग-लोक निर्माण विभाग (42 जनपदों में) एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (33 जनपदों में) योजना के कार्य संपादित कर रहें हैं।

• वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 79 पंचायत भवनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 54 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

• भारत सरकार द्वारा पंचायती राज के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2019-20 में ई-गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

8. औद्योगिक प्रगति

मुख्य बिन्दु

• वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में उत्तर प्रदेश गत् वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये दूसरी रैंक हासिल की है।

• प्रदेश के जनपदों के कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु सरकार द्वारा "एक

जनपद एक उत्पाद" (ओडीओपी) योजना 24-01-2018 को प्रारम्भ की गयी है। इस योजना हेतु वर्ष 2019-20 में रू 250.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया।

• वित्तीय वर्ष 2020-2021 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारम्भ करने जा रही है। इस योजना से युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा।

• उप्र सरकार ने उप्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये 'उप्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020' लागू किया है इसके अन्तर्गत उद्यमी को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा करने होंगें तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

• औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020' लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

• प्रदेश मे लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा हब) के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह स्थापित किया जाएगा।

• देश में कुल खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन में प्रदेश का 5 प्रतिशत का योगदान है।

9. सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

• प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 49.7 प्रतिशत हो गया है।

byjusexamprep.com

• प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 7.7% की वृद्धि हुई है।

• स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन के व्यापार, होटल एवं जलपान गृह खण्ड में वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 में कमशः 5.7 व 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

• प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011-12 में वित्तीय सेवाएं खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2019-20 में 3.4 प्रतिशत हो गया है।

• प्रदेश में मार्च, 2018 में सेवा क्षेत्र में 10.47 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे।

10.अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

मुख्य बिन्दु

• निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस -वे पर समाप्त होगा। "विश्वकर्मा" सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्बंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जायेंगे।

• प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण हेतु 2020-21 में मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलायी जा रही है।

• वर्ष 2020-21 में प्रदेश के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/ नवनिर्माण कराने के लिए 14 मार्गों के कार्यों हेतु माह अगस्त तक 10.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

• भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे है। आर्थिक रूप से

byjusexamprep.com

कमजोर परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ, प्रदेश के बलिया जनपद से किया गया था।

11.पर्यटन एवं नागरिक विमानन

मुख्य बिन्दु

• प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने हेतु "उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018" लागू की गयी है।

• कुम्भ 2019 प्रयागराज में 2394.70 लाख भारतीय एवं 10.30 लाख विदेशी सहित कुल 2405.00 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ/स्नानार्थ आए, जो कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।

• वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की 87.96 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी।

• हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ व वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थलों की यात्रा कराता है।

• पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को 24x7 ट्रैवल्स असिस्टेंस प्राप्त हो सकेगा।

• मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

12.शिक्षा

मुख्य बिन्दु

byjusexamprep.com

• उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

• इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में "लॉ यूनिवर्सिटी" की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

• जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोण्डा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना तथा आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

• प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2 लाख 65 हजार विद्यालय संचालित हैं ।

• प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम 'शारदा-स्कूल हर दिन आएं' संचालित किया है ।

13.स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मुख्य बिन्दु

• काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में “महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान", लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में "सुपर स्पेशिएलटी ब्लॉक" क्रियाशील हो चुके हैं।

• प्रदेश में 08 नये मेडिकल कॉलेज- हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर व मिर्जापुर का निर्माण कार्य चल रहा है। नये 13 मेडिकल कॉलेज-बुलन्दशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चन्दौली स्वीकृत हो चुके हैं।

byjusexamprep.com

• लखनऊ में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेन्टर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है।

• एसजीपीजीआई में एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्युदर मे सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत गिरावट लाने के लिये प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से एमएमआर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

• प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कन्ट्रोल रूम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

14.समाज कल्याण

मुख्य बिन्दु

• सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2020-21 (आय-व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रहा।

• वर्ष 2018-19 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का कमशः 7.5 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत रहा।

• समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' संचालित है।

byjusexamprep.com

• कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू 2500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है।

• प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आईटीआई) प्रारम्भ की गयी है।

15.श्रमशक्ति एवं सेवायोजन

मुख्य बिन्दु

• वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15-59 आयु वर्ग का प्रदेश की कुल जनसंख्या मे अंश 55.77 प्रतिशत है।

• बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं।

• प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2020-21 में सितम्बर, 2020 तक 1133 कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर 342043 प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गयी।

• प्रदेश में मार्च, 2019 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में 1601875 कर्मचारी कार्यरत थे।

• प्रदेश में मार्च, 2019 में महिला कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 0.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

• उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना' अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 44780 तथा वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक 1887 पंजीकृत महिला कर्मकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

byjusexamprep.com

16.सतत् विकास

मुख्य बिन्दु

• नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की।

• समग्र सुधार के शीर्ष तीन राज्यों मे उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है।

• लक्ष्य- 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मे प्रदेश की छलांग 40 अंकों की रही है।

• प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका में है।

• नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था।

• नीति आयोग के रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास में प्रतिस्पर्द्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है।

byjusexamprep.com